लखनऊ से प्रकाशित एवं लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा, बस्ती, उन्नाव, कानपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आजमगढ़, फतेहपुर, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर आदि जनपदों में प्रसारित

लखनऊ

वर्ष - 6 अंक - 1

रविवार 01 अगस्त 2021

पृष्ठ - 4

मूल्य - 2 रूपए

हिन्दी दैनिक

गायत्री विचार

आम जनता की आवाज

कोरोना से जान ... 4

न्यायपालिका में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर : उपराष्ट्रपति

एजेंसी, हैदराबाद

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने न्यायपालिका को देसी भाषा बोलने वालों के लिए सुलभ वातावरण बनाने की आवश्यकता का आह्वान किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की हालिया पहल में एक महिला को अदालत में तेलुगु में बोलने की अनुमति देने का उल्लेख करते हुए, इस घटना ने न्यायपालिका की आवश्यकता को रेखांकित किया है ताकि लोग अपनी मातृभाषा में अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकें और क्षेत्रीय भाषाएं में ही निर्णय भी दिए जा सकें। मातृभाषाओं के संरक्षण पर शनिवार को तेलुगु कूटामी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नायडू ने आगाह किया कि मातृभाषा के नुकसान से अंततः आत्म–पहचान और आत्म–सम्मान का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत के विभिन्न पहलुओं – संगीत, नृत्य, नाटक, रीति–रिवाजों, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान – को संरक्षित करना केवल अपनी मातृभाषा को संरक्षित करने से ही संभव हो पाएगा। नायडू ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और कायाकल्प के लिए अभिनव और सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया। इस बात पर जोर दिया कि भाषाओं को संरक्षित करना और उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है।

असम–नागालैंड सीमा विवाद

राज्यों ने विवादित जगह से पुलिस को हटाने के लिए एग्रीमेंट पर किए दस्तखत

एजेंसी, असम

असम–नागालैंड सीमा विवाद में सहमति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने दोनों राज्यों की पुलिस के वापस लौटने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने राज्य के बेस कैंप तक वापस चली जाएगी और यथास्थिति को बनाए रखेगी। इसी बीच मिजोरम पुलिस द्वारा खुद पर एफआईआर दर्ज करने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि ये बच्चों का काम है। जिस जगह झगड़ा हुआ था वो जगह असम की थी और है। इसलिए असम पुलिस का ही केस पर अधिकार बनता है। अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है तो अच्छा है। इस केस को एनआईए को सौंप देना चाहिए, ताकि वह जांच कर सके। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज असम और नागालैंड सरकारों के मुख्य सचिवों ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। दोनों सरकारों की पुलिस बॉर्डर क्षेत्र में जहां आमने सामने थी वो अपने राज्य के बेस कैंप तक लौटकर चली जाएगी और यथास्थिति बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट इमेज से यथास्थिति बनी रहे इस पर

सबकी नजर रहेगी। यह बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इसके लिए मैं नागालैंड के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।

ओबीसी सूची संबंधी राज्यों के अधिकार पर प्रहार हुआ : प्रवक्ता अभिषेक

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते समय केंद्र सरकार ने जो गलती की, उस कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची निर्धारित करने संबंधी राज्यों के अधिकार पर प्रहार हुआ। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दावा भी किया कि भाजपा सरकार की इस गलती की कीमत देश चुका रहा है, लेकिन भाजपा अपनी पीठ थपथापा रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''ओबीसी की सूची में किन जातियों को शामिल करना है, यह राज्यों का अधिकार था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ओबीसी की सूची में जातियों को शामिल करने के राज्यों के अधिकार में अतिक्रमण नहीं हो। उस वक्त के सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत और कई भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्यों का यह अधिकार लेने का कोई इरादा नहीं हैं।'' ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मतलब यह नहीं है कि ओबीसी की सूची में जातियों को शामिल करने या निकालने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। उसी गलती की कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। इसी का असर हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि ओबीसी की सूची सिर्फ एक होगी, राज्य स्तर की नहीं होगी।'' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की इस गलती ने देश के संघीय ढांचे पर आघात किया और राज्यों के अधिकारों पर प्रहार किया।

राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात

एजेंसी, नई दिल्ली

मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यहां राष्ट्रपति भवन में शनिवार को मुलाकात की। यह मुलाकात इस लिहाज से अहम मानी जा रही है कि सीमा पर विवाद के चलते पिछले सोमवार को मिजोरम पुलिस ने असम के अधिकारियों की टीम पर गोली चला दी थी, जिसमें असम पुलिस के पांच कर्मी और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी तथा पुलिस अधीक्षक समेत 50 अन्य घायल हो गए थे।

उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाके में की मुलाकात

एजेंसी,मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके पूर्ववर्ती एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कोल्हापुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके में मुलाकात की। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर के मुताबिक ठाकरे आज सुबह कोल्हापुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। ठाकरे को जब पता चला कि फडणवीस भी उसी इलाके में हैं, तो उन्होंने भाजपा नेता से मिलने के लिए एक संदेश भेजा। दोनों नेता शाहूवाड़ी में मिले और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल–चाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठाकरे ने कहा,''बाढ़ पीड़ितों के कल्याण के लिए तीन राजनीतिक दल शुरुआत से ही मेरे साथ हैं। यदि चौथा दल भी इन राहत कार्यों में शामिल होता है तो और भी बेहतर होगा।'' उद्धव ठाकरे शिव सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार के नेता हैं। फडणवीस ने ठाकरे से अपनी मुलाकात को लेकर कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया।

लल्लन सिंह को बनाया गया जदयू का नया अध्यक्ष

एजेंसी, बिहार

जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले साल दिसंबर महीने में आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन आरसीपी के मंत्री बनने के बाद नया अध्यक्ष बनाने को लेकर कयासों का दौर जारी था। जिसके बाद सियासी समीकरणों को साधते हुए ललन सिंह को यह पद दिया गया है। जदयू अध्यक्ष पद की रेस में ललन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी बताया जाता है। लोकसभा चुनाव में मुंगेर से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी को डेढ़ लाख से अधिक वोटों से हराकर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सांसद बने थे। इतना ही नहीं ललन सिंह जदयू के संसदीय दल के नेता भी हैं। राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने समीकरण साधने का प्रयास किया है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह एक ही जाति से आते हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष बनाकर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जदयू समाज के हर वर्ग का ख्याल रखती है।

गहलोत मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से पहले , कई मंत्री पद छोड़ने के इच्छुक : अजय माकन

एजेंसी, राजस्थान

कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल में कई मंत्रियों को हटाए जाने का स्पष्ट संकेत देते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि कुछ मंत्रियों ने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। माकन ने गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच यहां कांग्रेस व समर्थक विधायकों से एक–एक कर चर्चा करने के बाद यह बात कही। माकन ने विधायकों से फीडबैक लेने का काम बृहस्पतिवार को पूरा कर लिया था। माकन के अनुसार, हर किसी ने उनसे कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी उनके लिए तय करेगा वे उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। हालांकि, उन्होंने

किसी मंत्री विशेष का नाम नहीं लिया। वहीं, उनकी इस टिप्पणी को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कई मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। जो सरकारी पदों को छोड़कर संगठन के लिए काम करने को आतुर हैं। हमें ऐसे लागों पर गर्व है। सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों व हमारे ऐसे साथी जो सबकुछ छोड़कर संगठन के साथ काम करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर 2023 में कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता के अनुसार, मंत्रियों ने खुद उनका उदाहरण दिया जब 2013 में उन्होंने संगठन के लिए काम करने के वास्ते मंत्री पद छोड़ दिया था। अपनी रपट दिल्ली में आलाकमान को सौंपे जाने के बाद राज्य में बदलाव की संभावना के सवाल पर माकन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही दिल्ली हूं।

भारत व अमेरिका ने वैश्विक कल्याण का समझौता पांच साल के लिए बढ़ाया

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास में साझेदारी के लिए अपना समझौता और पांच साल के लिए बढ़ा लिया है। यह समझौता सहयोगी देशों को संयुक्त रूप से मदद मुहैया कराने के संबंध में है। इस समझौते के जरिये दोनों देश संपर्क बढ़ाने, कारोबार, निवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि के क्षेत्र में मदद मुहैया कराते हैं। यह समझौता त्रिकोणीय आधार पर है, जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा मदद पाने वाला देश भी भागीदार बनता है। स्टेटमेंट आफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सबसे पहले नवंबर 2014 में दस्तखत हुए थे। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती रही। 2026 में इस समझौते में संशोधन किया जाएगा। यह समझौता दोनों देशों को खासतौर पर एशिया और अफ्रीका में साथ मिलकर विकास कार्यो को करने का मौका देगा। इस समझौते के जरिये दोनों देश वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए कार्य करेंगे। आने वाले पांच साल के लिए हुआ यह समझौता कई उपलब्धियां हासिल करेगा। यह समझौता दोनों देशों के वैश्विक संपन्नता के लिए संकल्प को दर्शाता है। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एसजीपी के तहत हो रहे कार्यो की वार्षिक समीक्षा कर दोनों देश अपने सहयोग को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। इससे एक–दूसरे के प्रति हमारा विश्वास बढ़ रहा है।

दिल्ली के एक करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन : मुख्यमंत्री केजरीवाल

एजेंसी, नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में आज तक एक करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। ये एक करोड़ वैक्सीन 74 लाख लोगों को लगी हैं, इनमें से 26 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं और बाकी लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है। दिल्ली में लगभग 50 फीसदी आबादी को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगाने वाले स्टॉफ को बधाई दी और कहा कि उन्होंने जिस शिद्दत के साथ काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता में वैक्सीन लगवाने का उत्साह है। बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी 50–60 हजार वैक्सीन रोजाना लग रही है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो रोजाना 3 लाख वैक्सीन लगाने की हम क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के लिए हम केंद्र सरकार से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली को और बाकी के राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलना शुरू होगी। मुझे खुशी है कि हम अभी तक एक करोड़ वैक्सीन लगाने में सफल हुए हैं।

सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से लिया संन्यास

एजेंसी, पश्चिम बंगाल

आसनसोल से दूसरी बार जीतकर संसद पहुंचे बाबुल सुप्रियो ने अब राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार–1 और 2 में अब तक वह मत्री थे। हाल में ही हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया था। फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बना चुके बाबुल सुप्रियो 2014 में आसनसोल से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 2014 से 2016 तक वह शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे जबकि 2016 से 2019 तक उन्हें भारी उद्योग में राज्य मंत्री बनाया गया था। 2019 से 2021 तक वह पर्यावरण मंत्रालय में एमओएस रहे। बाबुल सुप्रियो हाल में ही संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी टॉलीगंज से अपनी किस्मत आजमाई थी। फेसबुक पर एक बड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं तो जा रहा हूँ..सब की बातें सुनी.. बाप, (माँ) पत्नी, बेटी, दो प्यारे दोस्त.. सब सुनकर कहता हूँ मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा।

सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने नेपाली आर्मी चीफ जनरल पूर्ण चंद्र थापा से बातचीत की

एजेंसी, नई दिल्ली

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान क्षेत्र में विकसित सुरक्षा परिदृश्य की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय सैन्य और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंदि्गत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह वार्ता दोनों देशों के बीच जारी सैन्य सहयोग के साथ–साथ इसे और विस्तार देने के तरीकों पर केंदि्गत रही। इस संबंध में सेना ने ट्वीट किया कि सीओएएस जनरल एमएम नरवने ने नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पहलुओं पर चर्चा की। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह वार्ता हुई।नेपाल इस क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंधों का हवाला देते हैं। गौरतलब है कि जनरल नरवणे ने पिछले साल नवंबर में काठमांडू का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने जनरल थापा सहित नेपाल के शीर्ष सैन्य और असैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की थी।

संपादकीय

पहाड़ों से छेड़छाड़ के घातक नतीजे

बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जनित घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई गांवों में बरसात तबाही लेकर आई। पहाड़ों की गोद में बसे कई गांव देखते ही देखते नजरों से लुप्त हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में पहाड़ खिसका और बस्ती मलबे में बह गई। रत्नागिरी के पोसरे बोद्धवाड़ी में भी तबाही हुई। राज्य के करजात, दाभोल, लोनावला आदि में पहाड़ सरकने से खूब नुकसान हुआ। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ के मलबे ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और सिलीगुड़ी से भी ऐसी ही खबरे हैं कि पहाड़ों का सीना काटकर जो सड़कें बनाई गई थीं, अब वहां बरसात के बाद मलबा बिछ गया है। ऐसी घटनाएं अभी बारिश के तीन महीनों में खूब सुनाई देंगी। जब कहीं मौत होगी तो कुछ मुआवजा बांटा जाएगा, लेकिन तबाही के असल कारणों को कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सुना है कि महाराष्ट्र सरकार अब पहाड़ के तले बसे गांवों को अन्यत्र बसाने की तैयारी कर रही है। पहाड़ खिसकने के पीछे असल कारण उस बेजान खडी संरचना के प्रति बेपरवाही ही होती है। पहाड़ खिसकने की त्रासदी का सबसे खौफनाक मंजर अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर देखा गया था। देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल, पानी बचाने की तो कई मुहिम चल रही हैं, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के आधार रहे पहाड़–पठारों के नैर्सिगक स्वरूप को उजाड़ने पर कम ही विमर्श हो रहा है। समाज और सरकार के लिए पहाड़ अब जमीन या धनार्जन का माध्यम बनकर रह गए हैं और पहाड़ अपने और समाज को सहेजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों–हजार साल में गांव–शहर बसने का मूल आधार वहां पानी की उपलब्धता होता था। पहले नदियों के किनारे सभ्यता आई, फिर ताल–तलैयों के तट पर बस्तियां बसने लगीं। किसी भी आंचलिक गांव को देखें, जहां नदी का तट नहीं है, वहां कुछ पहाड़ और पहाड़ के निचले हिस्से में झील तथा उसे घेरकर बसी बस्तियों का ही भूगोल दिखेगा। वहां के समाज ने पहाड़ के किनारे बारिश की हर बूंद को सहेजने तथा पहाड़ पर नमी को बचाकर रखने की तकनीक सीख ली थी। हरे–भरे पहाड़, खूब घने जंगल वाले पहाड़ जिन पर जड़ी–बूटियां, पक्षी और जानवर होते थे। जब कभी पानी बरसता तो पानी को अपने में समेटने का काम वहां की हरियाली करती, फिर बचा पानी नीचे तालाबों में जुट जाता। भरी गर्मी में भी वहां की शाम ठंडी होती और कम बारिश होने पर भी तालाब लबालब। बीते चार दशकों में तालाबों की जो दुर्गति हुई सो हुई, पहाड़ों पर हरियाली उजाड़ कर झोपड़–झुग्गी उगा दी गईं। नंगे पहाड़ पर जब पानी गिरता है तो सारी पहाडी काट देता है। अब तो पहाड़ों में पक्की सड़कें भी बनाई जा रही हैं। पहाड़ को एक बेकार–बेजान संरचना समझकर खोदा जा रहा है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि नष्ट किए गए पहाड़ के साथ उससे जुड़ा पूरा पर्यावरणीय तंत्र ध्वस्त होता है। अब गुजरात से देश की राजधानी को जोड़ने वाली 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को ही लें। अदालतें बार–बार चेतावनी दे रही हैं कि पहाड़ों से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन बिल्डर लाबी सब पर भारी है। कभी सदानीरा कहलाने वाले इस इलाके में पानी का संकट खड़ा हो गया है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई भी पर्वतमालाएं लें, खनन ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।`ल मार्ग या हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को मनमाने तरीके से बारूद से उड़ाने वाले इंजीनियर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि पहाड़ स्थानीय पर्यावास, समाज, अर्थव्यवस्था, आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं। पारंपरिक समाज भले ही इतनी तकनीक न जानता हो, लेकिन इंजीनियर तो जानते हैं कि धरती के दो भाग जब एक–दूसरे की तरफ बढ़ते हैं या सिकुड़ते हैं तो उनके बीच का हिस्सा संकुचित होकर ऊपर की ओर उठकर पहाड़ की शक्ल लेता है। जाहिर है कि इस तरह की संरचना से छेड़छाड़ के भूगर्भीय दुष्परिणाम उस इलाके के कई–कई किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं। पुणे जिले के मालिण गांव से कुछ ही दूरी पर एक बांध है।

भविष्य मोबाइल से दूर एक अकल्पनीय सच

दीपक सिंघल

31 जुलाई, 1995 को भारत में मोबाइल क्रांति शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम से इस दिन पहली बार मोबाइल कॉल कर बात की थी। अब जब असल मोबाइल दुनिया के रंग में आने के 50 साल जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं, तो सवाल वाजिब हैं कि दुनिया भर की उपयोगी चीजों यथा घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरे, पेजर आदि को गटक जाने वाला और लैपटॉप, सीडी प्लेयर को हजम करने की कोशिशों में लगे मोबाइल की उल्टी गिनती शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं। 31 जुलाई, 1995 को भारत में मोबाइल क्रांति शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम से इस दिन पहली बार मोबाइल कॉल कर बात की थी। वैसे दुनिया में 3 अप्रैल, 1973 को मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कपूर ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के एक कर्मचारी डॉ. जोएल एस. एंगेल से सबसे पहले मोबाइल पर बातचीत की शुरुआत की, पर यह बाजार में 10 साल बाद यानी 1983 को आया। अब जब असल मोबाइल दुनिया के रंग में आने के 50 साल जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं, तो सवाल वाजिब हैं कि दुनिया भर की उपयोगी चीजों यथा घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरे, पेजर आदि को गटक जाने वाला और लैपटॉप, सीडी प्लेयर को हजम करने की कोशिशों में लगे मोबाइल की उल्टी गिनती शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं? जबाव है– मुट्ठी से तकदीर, मां और जीवनसाथी के हाथ को जुदा कर दुनिया को अपने तक सीमित कर देने वाले मोबाइल के मौजूदा रूप के भी ज्यादा दिन शेष नहीं हैं, शायद 10 वर्ष! हो सकता है कि यह अपने बदले हुए अवतारों में अगले 30 वर्षों तक जिंदा रहे, लेकिन 2050 आने तक शायद कोई इसका नामलेवा भी ना हो. ..कैसे? आइये जानने व समझने के प्रयास करते हैं। यकीन मानिए, मोबाइल को सबसे पहली पटखनी यही सेगमेंट देने वाला है। करीब 2002 में जब सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक से मिला था, तो उन्होंने तंज कसा था कि आधुनिक इंसान का एक हाथ जेब ने जकड़ लिया था, दूसरा अब मोबाइल ने। यानी समस्याएं शुरुआत से ही नजर आने लगी थीं। हालांकि, यह बहुत शुरुआती दौर था और तब मोबाइल चंद इंसानों के पास ही मौजूद थे। कॉल करना बेहद महंगा था। फिर भी, समझदारों को अंदाजा नहीं था कि मोबाइल देखते ही देखते इतना हाईटेक हो जाएगा कि हाथ में दुनिया समा जाएगी और घर–परिवार की शांति, आपसी बातचीत, चिड़ियां और लगभग सब कुछ भी गेमिंग, टिकटाक, वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की भेंट चढ़ जाएंगे। चूंकि, तकनीक उम्मीदों से भी कहीं तेज रफ्तार से परवाज भर रही है, इंसान व्यस्त दर व्यस्त होता जा रहा है।

बंगाल में लोकतंत्र का जनाजा

प्रकाश सिंह

यह बड़ी विडंबना है कि रवींद्रनाथ टैगोर के प्रदेश में, जहां प्रख्यात कवि ने यह कल्पना की थी कि मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा, मस्तिष्क भयमुक्त होगा और जहां समाज टुकड़ों में नहीं विभक्त होगा, उसी राज्य में हजारों लोगों के साथ हत्या, दुष्कर्म, पलायन और धमकी इत्यादि की घटनाएं पिछले कुछ महीने में हुई हों।' इन शब्दों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने बंगाल में चुनाव बाद की हिंसक घटनाओं की जांच का निष्कर्ष निकाला है। विडंबना यह है कि ममता सरकार इस निष्कर्ष को सिरे से खारिज कर रही है। अभी दिल्ली आईं ममता बनर्जी ने चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को भाजपा का ड्रामा करार दिया। ज्ञात हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार एनएचआरसी ने बंगाल में चुनाव पश्चात हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सात टीमों ने बंगाल के सभी जनपदों का दौरा कर मामलों की गहराई से पड़ताल की। समिति को कुल 1,979 शिकायतें मिली थीं, जिनमें करीब 15,000 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। जांच से जो तथ्य आए हैं, उन्हें किसी भी चश्मे से देखा जाए, वे अत्यंत भयावह हैं। देश में चुनावों के दौरान अनियमितताओं की शिकायत तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बार्द ंहसा के लिए कुख्यात प्रदेशों में भी शांति हो जाती थी और लोग नई सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। किसी ने पक्ष में वोट डाला हो या विपक्ष में, बाद में कोई मारपीट नहीं होती थी। इसके उलट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने छांट–छांटकर उन लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की, जिन्होंने अन्य पार्टी को वोट दिया। एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में आपराधिक तत्वों, जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, ने सुनियोजित और व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया।' प्रतिशोध की भावना से हिंसा हुई, जिसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल को निशाना बनाया गया, जिससे हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ और उन्हें भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सदस्यों को यह देखकर दुख हुआ कि इन घटनाओं की स्थानीय नेताओं द्वारा निंदा करना तो छोड़िए, बल्कि मौके पर भी नहीं गए और ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, जिससे लोगों का कष्ट कम हो सके। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पुलिस के बारे में लिखा है कि वह या तो लापरवाह थी या इन सब कृत्यों में उसकी मिलीभगत थी। फलस्वरूप तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। संपूर्ण प्रदेश से जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनमें अधिकतम कूचबिहार (322) से मिलीं। दूसरे स्थान पर बीरभूम (314) रहा। इन शिकायतों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हत्या की 29 घटनाएं थीं, दुष्कर्म की 12, गंभीर चोट की 391, आगजनी की 940 और धमकी की 562। जांच कमेटी ने पाया कि पुलिस ने बहुत सी शिकायतों को दर्ज नहीं किया और जो शिकायतें दर्ज हुईं, उनमें घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारियां बहुत कम हुईं। बहुत से मामलों में सही धाराएं नहीं लगाई गईं और ऐसा प्रतीत हुआ

कि अपराध को कम करके दर्ज किया गया। सभी एफआइआर में 9,304 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए। इनमें केवल 1,354 (14 प्रतिशत) की गिरफ्तारी की गई। इन गिरफ्तारियों में 1,086 (80 प्रतिशत) को जमानत मिल गई। कुल मिलाकर आरोपित व्यक्तियों में केवल तीन प्रतिशत जेल में पाए गए, शेष 97 प्रतिशत खुले घूम रहे।

स्वास्थ्य पर प्रभावी निवेश जरूरी

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में गैर सरकारी संगठन जनस्वास्थ्य अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयुक्त प्रबंधन न होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। देश की 70 फीसदी स्वास्थ्य सुविधाएं निजी हाथों में है। निजी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का शोषण कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं सभी राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसमें दो मत नहीं हैं कि कोरोना संक्रमण से निर्मित स्वास्थ्य संकट देश के लिए मानवीय, सामाजिक और आर्थिक संकट में परिवर्तित हो गया है। इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और देश की विकास दर में कमी आई है। निस्संदेह इस समय स्वास्थ्य से जुड़े मानवीय संसाधन, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी चिंताजनक रूप में दिखाई दे रही है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश में 854 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर और 559 लोगों पर एक नर्स उपलब्ध है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि अस्पतालों में बेड उपलब्धता के लिहाज से 167 देशों में भारत 155वें स्थान पर है और देश में प्रति 10,000 की आबादी पर करीब पांच बेड हैं। भारत में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए उच्च–स्तरीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को वर्ष 2024 तक सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के करीब 0.95 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत तक किए जाने की बात कही है। हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बुनियादी उपलब्धियां हासिल की हैं। कई महामारियों पर नियंत्रण हुआ है। देश में 1990 में औसत आयु 59.6 वर्ष थी, जो 2019 में बढ़कर 70.8 वर्ष हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गरीबों तक पूर्व उपचार और उपचार बाद देखभाल की पहुंच के रूप में असमानता को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। 'आयुष्मान भारत' योजना स्वास्थ्य सेवा के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को मुहैया कराया जाए। कोविड–19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का व्यय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अब भी देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सबको कोरोना टीकाकरण के लिए अधिक संसाधनों और रणनीतिक प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्वास्थ्य पर खर्च को गरीबी बढ़ाने वाला प्रमुख कारण माना जाने लगा है। ऐसे में, सुदृढ़ स्वास्थ्य ढांचे के लिए असाधारण प्रभावी निवेश जरूरी है।

यूनेस्को और धोलावीरा : कच्छ के रेगिस्तान में 5 हजार साल पुरानी मुंबई

दयाशंकर शुक्ल सागर

भारत को इतिहास लिखने में कभी भरोसा नहीं रहा। भारत के पास अपना कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं है। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, किस्से हैं कहानियां हैं, नाटक हैं लेकिन सहेजा हुआ इतिहास नहीं है। जैसा कि मैगस्थनीज ने ईसा से कोई 400 साल पहले सिकन्दर के वक्त श्इंडिकाश लिखी। शायद हम हिन्दुस्तानी वर्तमान में जीने वाले लोग थे। खाओ–पियो मस्त रहो टाइप। जो हो चुका उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। पुरानी स्मृतियां क्या संभाल के रखना। भारत ने जिस चीज को मूल्य दिया वो चीज थी संस्कृति। इसे हमने बचाए रखा। मिस्त्र खत्म हुआ, यूनान खत्म हुआ, सीरिया, बेबीलोन दुनिया की सारी संस्कृतियां पैदा हुई और मर गईं। लेकिन हमारी संस्कृति अभी तक जिंदा है। पता नहीं ये गर्व करने की बात है कि नहीं। क्योंकि इंसानों की तरह संस्कृतियां और सभ्यताएं पैदा होती हैं और एक दिन मर जाती हैं। फिर नई सभ्यता विकसित होती है जो बेशक पुरानी सभ्यता से और अधिक उन्नत और उम्मीद से भरी होनी चाहिए। यूनेस्को ने गुजरात के सिंधु–हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक शहर धोलावीरा के अवशेषों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। धोलावीरा ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। चार साल पहले गुजरात गया था तो बड़ा मन था कि यहां भी एक चक्कर लगा लूं। लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। सोमनाथ मंदिर से आगे नहीं जा पाया। दोबारा प्लान बना कि कि हवाई जहाज से कच्छ के पुराने ऐतिहासिक पाटनगर भुज हवाई अड्डे पर उतरा जाए। लेकिन यहां से भी धोलावीरा कोई 300 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि एयरपोर्ट से सड़क मार्ग पक्का है। लेकिन इस बार भी बात नहीं बन सकी। तीसरी दफा फिर कार्यक्रम बना तो पता चला कि अब वहां जाने पर रोक लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान के सीमा होने के कारण इस इलाके में दाखिल होने के लिए बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स से इजाजत लेनी होगी, पर अब धोलवीरा के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद शायद सरकार इस दिशा में कोई नया कदम उठाए। खैर, गुजरात के कच्छ के रण यानी रेगिस्तान को श्नमक का रेगिस्तानश कहा जाता है। कोई 23,000 वर्ग फीट में फैला ये वीरान इलाका कभी समुंदर का हिस्सा था। लेकिन आज से कोई पांच हजार साल पहले ये इलाका समुंदर के किनारे कोई 150 एकड़ इलाके में बसा एक शानदार महानगर हुआ करता था। आज की मुम्बई की तरह। शायद उससे कहीं उन्नत और सम्पन्न। दरअसल, इस सभ्यता के स्वर्ण काल में समुंदर के रास्ते भारतीयों का मैसोपोटेमिया से व्यापार होता था। यह महानगर तब बसा था जब वेद, पुराण और उपनिषद नहीं लिखे गए थे। तब तक न सिकन्दर विश्व विजय के लिए निकला था और न महात्मा बुद्ध का युग शुरू हुआ था। ये शहर प्राचीन संस्कृत भाषा से भी सदियों साल पुराना था। इस शहर की अपनी लिपि और अपनी भाषा थी जिसे आज तक कोई विद्वान नहीं पढ़ सका है। इस शहर के तबाह हो जाने के हजारों साल बाद सिकन्दर कोई 327–325 ईसा पूर्व के बीच विश्व विजय से थका–हारा घर वापसी के वक्त सिन्ध नदी की यात्रा करते हुए इस इलाके में आया था। तब इस इलाके में छोटे छोटे खूबसूरत द्वीप हुआ करते थे। मीठे पानी की बड़ी झीलें भी थीं। सिकन्दर के हमसफर दोस्त नियार्खस ने अपनी डायरी में लिखा कि किस तरह कच्छ के लोगों की मदद से सिकन्दर ने समुंदर का रास्ता पार करने के लिए उनसे करीब 800 बड़ी नावें बनवाईं। लेकिन काम नहीं बन पाया और उसे दूसरे रास्ते से लौटना पड़ा। और हैरत की बात देखिए कच्छ के निवासी 5000 साल से लेकर आज तक अच्छे नाविक माने जाते हैं। राबर्ट सिवराइट, रशब्रुक और मिसेज पोस्टन तक ने कच्छ के रण पर बेहतरीन किताबें लिखीं। सब ने ये बात लिखी। जहांगीर ने तो कच्छ के लोगों का लगान इस शर्त पर माफ कर दिया था कि वे गरीब लोगों को पानी के जहाज से मुफ्त में मक्का और मदीना की यात्रा कराएंगे। 1838 में पोस्टन ने कुछ पुराने कच्छ नाविकों से बातचीत में निकाला कि वे अपने जहाज खुद बनाते थे और अपने बनाए समुद्री नक्शों पर ही यात्रियों को जहाज से इंग्लैंड, पोलैंड से लेकर अफ्रीका तक की यात्राएं कराते थे। कच्छ के कई कुख्यात समुन्द्री डाकू भी हुए। ये कंपनी के जहाज लूट लेते। इन्होंने समुन्द्र के रास्ते से आने वाले फिरंगियों को पानी पिला दिया था। इन्हें स्थानीय राव राजाओं का संरक्षण था। इन्हीं के दम पर राव ने 1818 में कंपनी से समझौता किया कि वे इन दस्युओं से कंपनी को बचाएंगे बदले में कंपनी उनके स्वशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।खैर, ये तो है इस इलाके की ऐतिहासिकता। इसी इलाके की 20वीं सदी की कहानी सुनिए। कच्छ में एक पिछड़ा उजाड़ गांव है धोलावीरा। मजे की बात ये है कि इस शहर की खोज से पहले कच्छ के लोगों ने

गुजरात को भी अपना नहीं माना था। आजादी के दस साल बाद तक कच्छ गुजरात का हिस्सा न होकर एक केन्द्र शासित राज्य था। यहां के स्थानीय लोगों की अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता है। ये लोग आदिम टोटम नाग, राक्षस, यदु, सिन्धी से लेकर ग्रीक देवताओं को अपना मानते रहे हैं। वे आज भी भारत को तो अपना मानते हैं लेकिन गुजरातियों को अपना नहीं समझते।सदियों की हवाओं ने उड़ते–उड़ते इस प्राचीन नगर के ऊपर से रेत की चादर जरा सी सरका दी थी। गांव वाले बरसों से एक कच्ची पक्की ईंटों के खंडहर के नजदीक रह रहे थे। वे नहीं जानते थे कि ये खंडहर कितने पुराने हैं। उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था ।

302 किलोमीटर लंबा होगा मेरठ से गुजरने वाला आर्थिक गलियारा

संवाददाता

मेरठ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अपनी फेसबुक वाल पर पोस्ट शेयर कर आर्थिक गलियारे के फायदे बताए। अगले पांच वर्षों में मेरठ परिवहन साधनों के साथ औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। इसी के चलते मेरठ को आर्थिक गलियारे में शामिल किया गया है। भारतमाला परियोजना के फेज–प्रथम आर्थिक गलियारे में मेरठ भी है। मेरठ को बिलासपुर (पंजाब के मोगा जिले में) से दिल्ली रूट में शामिल किया गया है। आर्थिक गलियारे में शामिल होने से सामान को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए कई विकल्प मौजूद होंगे। देश के 44 आर्थिक गलियारे में बिलासपुर–दिल्ली रूट भी है। इसे 302 किलोमीटर में बनाया जाना है। इसकी शुरुआत कई एक्सप्रेस–वे को जोड़कर की जानी है। जिनका निर्माण भी चल रहा है। इसमें दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे मुख्य प्रोजेक्ट हैं। आर्थिक गलियारे में उच्च गति के परिवहन नेटवर्क को विकसित करने की तैयारी है। इसी को देखते हुए भारतमाला परियोजना के तहत इसकी तैयारी की जा रही है। जिससे आपस में प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी कम समय में हो सके। इससे सामान का आवागमन कम दाम में तेज रफ्तार के साथ हो सकेगा। इससे समय की बचत होगी। वहीं, देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में परिवहन का योगदान हो सकेगा। आर्थिक गलियारे को कई भागों में बनाया जा रहा है। इसमें इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड भी शामिल है। इसमें करनाल–मेरठ मार्ग को भी शामिल किया गया है। इसे 101 किमी की फीडर रोड में शामिल किया गया है। एक या दो कॉरिडोर को आपस में जोड़ने वाली सड़क को फीडर रोड कहा जाता है। इसी को देखते हुए मेरठ–करनाल मार्ग को शामिल किया गया है। ये मार्ग पंजाब सहित उत्तर प्रदेश में आने वाली सड़क को आपस में जोड़ता है।

मार्ग दुर्घटनाओं में बालक समेत दो की मौत

संवाददाता

बहराइच। जिले में अलग–अलग स्थानों पर हुई मार्ग दुर्घटनाओं में बालक व महिला की मौत हो गई। जरवलरोड में अनियंत्रित ट्रक पुल से टकरा गया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के कल्यानपुर निवासी 50 वर्षीय जौहरी अपने बेटे रामू व बहू के साथ बाइक से रिश्तेदारी में मुसल्लमपुर जा रही थीं। रामगांव थाना क्षेत्र के बेगमपुर बाजार पहुंचने पर सामने से सांड़ के आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई। महिला सड़क

पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। एसओ अभय सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।थाना क्षेत्र में दुजईपुरवा के पास हाईवे पार कर रहे गांव निवासी कैलाश के आठ वर्षीय पुत्र डबलू को बाइक सवार ने ठोकर मार दिया। इलाज के लिए घायल बालक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

डीएम के आदेश पर दुकान–दुकान पहुंचे अफसर

संवाददाता, अमेठी। उर्वरक की दुकानों पर गड़बड़ी की शिकायत पर हरकत में आए जिला प्रशासन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 44 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां पाये जाने पर 17 दुकानों से नमूने एकत्र किये गए। वहीं स्टाक रजिस्टर व स्टाक आदि का मिलान न होने पर एक दुकान को निलंबित कर दिया गया। साथ ही चार दुकानदारों को कमियों को दूर करने का अवसर देते हुए नोटिस

दी गई है। धान की रोपाई के चलते खाद व उर्वरक की मांग तेज हो गई है। किसानों को उर्वरक के लिए मशक्कत झेलनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर निर्धारित रेट से ज्यादा तो कहीं मिश्रित उर्वरक की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। किसानों की समस्या को देखते हुए डीएम अरुण कुमार ने जिले में स्थित उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि सभी तहसीलदार व कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई दुकानों पर नियमानुसार व्यवस्था नहीं पाई गई। कहीं स्टाक मौके पर नहीं मिला तो कहीं ई–पास मशीन में ही खराबी पाई गई। जिस पर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकानदारों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री करने, जमाखोरी रोकने, यूरिया के साथ अन्य प्रोडक्ट की टैगिग न करने तथा दुकानों पर स्टाक रजिस्टर दुरुस्त रखने सहित कई अन्य हिदायतें दी गईं। उन्होंने बताया कि किसानों को सही उर्वरक उपलब्ध होगा। दुकानदारों द्वारा अन्य प्रोडक्ट की टैगिग करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

दहेज हत्या के तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा

संवाददाता

बलिया। एएसजे तृतीय के न्यायालय ने दहेज हत्या के तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर रही है। मॉनिटरिग सेल अभियोजक व संयुक्त निदेशक अभियोजन की पैरवी पर न्यायालय एएसजे तृतीय दिनेश कुमार मिश्रा ने अभियुक्त सुनील चौहान, जय राम चौहान व सुशीला उर्फ हौशिला पत्नी जयराम निवासी बैरिया को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को एक–एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्जीय एटीएम हैकर गैंग को पकड़ा, चालीस लाख की कर चुके हैं ठगी

संवाददाता

कानपुर। कानपुर में पुलिस ने एटीएम हैंकर गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये लोग सूनसान इलाके में आने वाले एटीएम को हैक कर लोगों को ठगते थे। इन निशाने पर ज्यादा तार गरीब तबके लोग होते थे। जिन्हें रुपयों की अधिक जरूरत होती थी। पकड़े गए तीनों आरोपित जालौन रहने वाले है। जो अब चालीस लाख तक ठगी कर चुके हैं। इनके पास से 206 एटीएम कार्ड और साढ़े पांच लाख रुपये नकदी भी बरामद हुई है। नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक तीनों आरोपित शहर छोडने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए। आरोपितों की पहचान जनपद जालौन के थाना कालपी अंतर्गत देवकली गांव निवासी रवि कुमार, नन्द किशोर व खिलौली गांव निवासी प्रमोद

कुमार के रूप में हुई है। तीनों आरोपित किसी के भी नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर या रकम का झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड हासिल कर लेते थे। यह खाते सब्जी वाले, कबाड़ी वाले या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे पैसे की जरूरत होती थी। हैकर उसे चार से पांच हजार रुपये देकर कार्ड लेते थे। साथ ही उसका डेबिट कार्ड पिन कोड लेते थे। एटीएम से कैश निकालते समय मशीन के कैश शटर को पकड़ कर रखते थे। कैश तो निकलकर आ जाता था, लेकिन शटर से छेड़छाड़ करने से ट्रांजेक्शन डिक्लाइन का मैसेज आ जाता था। उसके बाद बैंक के टोल फ्री नंबर पर बात करके शिकायत दर्ज करते थे कि बैंक खाते से पैसा कट गया है पर एटीएम से पैसा नहीं निकला। इसके बाद बैंक उस पैसे को रिफंड कर देती थी। आरोपितों के पास कई सारे खाते होने के कारण डेबिट कार्ड का पिन याद रखने के लिए कार्ड के सीवीसी में एक अंक जोड़ कर लिख देते थे, जिससे एटीएम का पिन आसानी से याद रहे। एटीएम लेने के बाद यह लोग अन्य राज्यों जनपदों में जाकर घटना को अंजाम देते थे।

तालाब में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

संवाददाता

उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के गांव बाबा खेड़ा बस्ती के अंदर स्थित एक तालाब में महिला का शव पानी में उतराता हुआ ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवा कर शिनाख्त कराने के प्रयास किए। लेकिन पहचान नहीं हो सकी। बाबाखेड़ा गांव में आबादी से लगा हुआ अतरा तालाब है। शुक्रवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे तालाब से काफी तेज दुर्गंध आने पर लोगों को कुछ संदेह हुआ। ग्रामीणों ने करीब जाकर देखा तो बीच में एक महिला का औंधे मुंह शव पानी में उतराता हुआ दिखाई पड़ा। इसपर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका कत्थई रंग का ब्लाउज व महरूम रंग का पेटीकोट पहने है। साथ ही हाथों में चूड़ियां तथा गले में लाकेट भी पड़ा है। मृतका की उम्र करीब 40 साल के आसपास बताई जा रही है। शव पांच छह दिन पुराना लग रहा है। उसकी गला दबा कर हत्या कर शव को तालाब में दबा दिया गया। बारिश के चलते पानी बढ़ने से शव ऊपर आ गया है। थानाध्यक्ष माखी राजेश सिंह ने बताया कि शव कि शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ससुराली जनों ने घर से निकाल दिया। पीड़िता ने थाने पहुंच कर पति सास, ससुर, देवर, ननद सहित छह ससुराली जनों के खिलाफ तहरीर दी है।

डीएम कार्यालय के बाहर दंपती ने किया आत्मदाह का प्रयास, सिटी मजिस्ट्रेट पर लगाया आरोप

संवाददाता

रायबरेली। कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के हाथ–पैर उस वक्त फूल गए, एक जब दंपती ने डीएम दफ्तर के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उन्हें पकड़ा। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब पीड़ित शांत हुए। मामला महराजगंज तहसील के मांझगांव मजरे जमुरावां का है। यहां के रहने वाले जीत बहादुर सिंह सुबह पत्नी रामलली, दो बेटों सूर्य प्रताप व रौनक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। फरियाद लिखे पत्र के साथ एक बोतल में पेट्रोल भी लेकर आए थे। पति–पत्नी का आरोप है कि यहां आकर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह से अपनी समस्या बताई तो वे उल्टे उन्हीं को धमकाने लगे। दुर्व्यवहार भी किया।

इससे गुस्साए जीत बहादुर ने पेट्रोल की बोतल निकाल ली और आत्मदाह करने की कोशिश की। आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रकरण डीएम वैभव श्रीवास्तव तक पहुंचा तो वे भी आ गए और हालात संभाले। भाजपा नेता करा रहा कब्जा रू जीत बहादुर सिंह का कहना है कि हलोर–सेमरौता रोड पर उनकी पुश्तैनी जमीन है। आबादी में दर्ज इसी भूमि पर उनका मकान बना है। इस जमीन में तीन भाइयों का हिस्सा है। एक भाजपा नेता ने बहलाफुसला कर दो भाइयों की जमीन लिखवा ली। अब पीड़ित के हिस्से की भूमि पर भी कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर वे महराजगंज एसडीएम के पास दो दिन गए, लेकिन वहां से लौटा दिया गया। जनता दर्शन में मामला आया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं। हां, अब प्रकरण संज्ञान में आया है। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को बुलाया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।

नाला व बंजर भूमि पर बनाई गई चहारदीवारी पर चला बुलडोजर

संवाददाता

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में नाले व बंजर भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर शुक्रवार की शाम प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। सदर तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल के आदेश पर राजस्व प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई चहारदीवारी को ध्वस्त करा दिया। पीड़ित जयसिंह मौर्य ने का आरोप है कि जिला प्रशासन ने मनमानी कार्रवाई करते हुए उसके साथ ज्यादती की है। उनका कहना है कि यह निर्माण उन्होंने उस आराजी पर कराया था जो उनकी दादी सुखा देवी पत्नी राम नारायण के नाम दर्ज है। प्रशासन ने कार्रवाई से पूर्व कोई सूचना भी नहीं दी। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन के क्रम में सायंकाल कानूनगो व क्षेत्रीय लेखपाल बड़ी संख्या में पुलिस बल व नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर भगौतीपुर गांव पहुंचे। नाले व बंजर भूमि पर जयसिंह मौर्य की बनवाई गई चारदीवारी को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। जयसिंह मौर्य का आरोप है कि चारदीवारी गिराए जाने के समय राजस्वकर्मी मांगे जाने पर किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं दिखाए। राजस्व प्रशासन की ओर से पूर्व में कोई नोटिस भी जारी नहीं की गई थी।

महिला और तीन बच्चों की हत्या में आरोपित अंशुल गिरफ्तार

संवाददाता

आगरा। महिला और तीन बच्चों की हत्या में आरोपित 25 हजार का इनामी अंशुल शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे महिला के चांदी के गहने, आधार कार्ड और सात सौ रुपये बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपित समेत दो को जेल भेज चुकी है। अब गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली के कूचा साधूराम में 21 जुलाई को रेखा, उनका बेटा वंश, पारस और बेटी माही की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 22 जुलाई को शव घर में पड़े मिले। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 27 जुलाई को पुलिस ने रेखा के रिश्ते के भाई संतोष और उसके दोस्त वीरू को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। जबकि तीसरा आरोपित सीता नगर निवासी अंशुल राठौर फरार था। पुलिस के अनुसार, संतोष ने रेखा के उधार रुपये न चुकाने और घर से लूटपाट करने के लिए चार हत्याएं की थीं। लालच देकर उसने अपने दोस्त अंशुल और वीरू को भी घटना में शामिल किया था। एसएसपी मुनिराज जी. ने फरार अंशुल राठौर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

6,635 लोगों ने कराया टीकाकरण

संवाददाता

कन्नौज। कोरोना की संभावित स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की गति तेज कर दी है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाक्टर गीतम सिंह ने बताया कि जिले के 11 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। 4363 युवाओं समेत 6635 लोगों का टीका लगा है। जिसमें 18–44 वर्ष के 4363 व 45 के ऊपर 2272 लोगों को टीका लगाया गया। कन्नौज सीएचसी में 883, जिला अस्पताल 170, जलालाबाद 504, गुगरापुर 330, तालग्राम 726, 100 शैय्या अस्पताल 170, छिबरामऊ सीएचसी 869, सौरिख 455, हसेरन 1032, उमर्दा 1328 व मेडिकल कालेज में 168 लोगों को ही टीका लगाया है। जिला कोल्ड चौन मैनेजर ने बताया कि कोविशील्ड 10 हजार व कोवैक्सीन 5520 डोज है। टीका लगा नहीं और मैसेज आ गया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसा ही मामला जिला अस्पताल का है। कन्नौज निवासी सुधा देवी महिला ने जिला अस्पताल के मैटरनिटी विग पहुंची। यहां उन्होंने यह आरोप लगाकर हंगामा किया कि उनके टीका लगा नहीं, इसके बाद भी उनके मोबाइल में टीकाकरण होने का मैसेज आ गया। 27 जुलाई को वह टीकाकरण कराने के लिए आईं थीं। यहां पंजीकरण किया, मगर भीड़ अधिक न होने के कारण वह घर वापस चली गई। इसके बाद मोबाइल पर वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और हंगामा किया। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम में फोन कर शिकायत की।

नए खुलेंगे 206 स्वास्थ्य उपकेंद्र, गांव में ही मिलेंगी सुविधाएं

संवाददाता, गोंडा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों के बीच अब जिले में 206 नए उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे गांवों में रह रही महिलाओं व बच्चों को टीकाकरण व अन्य सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों का निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में वर्तमान समय में 322 उपकेंद्र है। ऐसे में आए दिन समय से सुविधाओं के न मिलने की शिकायत मिल रही है। अब स्वास्थ्य विभाग ने पांच हजार की जनसंख्या पर उपकेंद्र स्थापना को मंजूरी दी है। ऐसे में जिले में 206 नए उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इन गांवों की आबादी 5 हजार से अधिक है। बभनजोत में 14, बेलसर में 15,छपिया में 8, कर्नलगंज में 8, हलधरमऊ में 13, इटियाथोक में 15, काजीदेवर में 16, कटरा बाजार में 15, मनकापुर में 13, मुजेहना में 15, नवाबगंज में 10, पडरीकृपाल में 9, परसपुर में 16 के अतिरिक्त रुपइडीह, तरबगंज, वजीरगज में उपकेंद्र बनाए जाने हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसके लिए सीएमओ को पत्र लिखा है। इनसेट किराए पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए मानक तय किए गए हैं। आवश्यक संसाधनों के साथ ही इसे गांव के समीप होना चाहिए। इसे बाद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बदलने की तैयारी है। इसके लिए तीन हजार रुपये किराया तय किया गया है। इसके चिन्हांकन के लिए ग्राम प्रधान का सहयोग लिया जा सकता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर गर्भवती व बच्चों के टीकाकरण के साथ ही अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। विभाग की अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। भगहर बुलंद में आयोजित टीकाकरण सत्र में गर्भवती के स्वास्थ्य की जांच की गई। पांच हजार की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जानी है। इसके लिए विभाग से निर्देश मिले हैं। इसके अनुरूप प्रभारी चिकित्साधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 10-10 लाख आर्थिक सहायता

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गवाने वाले 50 पत्रकारों के परिवारीजन को शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ 10–10 लाख रुपये का चेक देंगे। राज्य सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद दी जाएगी। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में 14 और वर्ष 2021 में 36 में पत्रकारों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर बहुत से पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी है। अपार संकट की इस घड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल की है।

कोरोना काल में मीडिया की भूमिका सराहनीय, दिवंगत पत्रकारों को नमन : सीएम योगी आदित्यनाथ

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के दौरान दिवंगत होने वाले उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ ही पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की। लोक भवन में उन्होंने एक कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत 55 पत्रकारों के परिवार को दस–दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जिन पत्रकारों ने अपना जीवन कोरोना काल मे गवाया है उन सभी को मेरी संवेदना व श्रद्धांजलि है। आज हम सबके लिए यह एक ऐसा क्षण है जब मीडिया जगह से जुड़े हुए उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति जिन्होंने कोरोना कालखंड में समाज के लिए अपनी लेखनी को चलाते–चलाते अपने प्राणों की आहूति दी है, उन सबके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें, श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें और परिवारजनों के प्रति एक संबल बन सके।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है। इस दौरान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कोरोना से पस्त हुई। इस संकट में भी हमने सभी को सुरक्षित घर पहुचाने का काम किया। हमने कोरोना वायरस की पहली लहर को नियंत्रित करने के साथ ही प्रदेश में वैक्सिनेशन शुरू कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम लगभग कोरोना को नियंत्रित करने के नजदीक है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता ये कब वापस आ जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 15–16 महीने से पूरा देश, पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है, हर तबका इस संक्रमण से प्रभावित हुआ है। योगी ने कहा कि जब पहली लहर को हमने एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया, तभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने उत्तर प्रदेश में वैक्सिनेशन के वेस्टेज को पूरी तरह रोका।

ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, यूपी में 4 लाख कुपोषित

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश को फतह करने का सपना देख रहे हैं। इसी बीच उन्होंने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख तीव्र कुपोषित बच्चे हैं। हजारों में डॉक्टरों के पद खाली हैं। एएनआई के मुतादिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख तीव्र कुपोषित बच्चे हैं। हजारों में डॉक्टरों के पद खाली हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बंद पड़े हैं। एक–एक चीज का जवाब (योगी आदित्यनाथ) दें। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के जाने के बाद असम और मिजोरम की पुलिस पर फायरिंग होती है। ये सरासर बीजेपी की नाकामी है। गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि देश में छह माह से छह साल की उम्र के 9 लाख से अधिक अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है जिनमें से 3,98,359 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं।

यूपी में कोरोना केस घटने के बाद भी टेस्टिंग नहीं हो रही कम, वैक्सीनेशन कार्य निरन्तर जारी

गायत्री विचार ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमण कम होने के बावजूद, टेस्टिंग कम नहीं की जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,51,265 सैम्पल की जांच की गयी है, 1,31,973 सैम्पल जनपदों से आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भेजे गये है। प्रदेश में अब तक कुल 6,55,02,631 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32 नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 48 लोग तथा अब तक कुल 16,84,973 लोग कोविड–19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड–19 से ठीक होने का प्रतिशत 98.6 चल रहा है। प्रदेश में कोरोना के कुल 712 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 452 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में प्रतिदिन की संक्रमण दर 0.01 प्रतिशत के आस–पास है। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में 8,21,468 वैक्सीन की डोज दी गयी है। कल तक पहली डोज 3,99,11,639 दी गयी है जो आज आज 04 करोड़ से अधिक हो गई है। दूसरी डोज 76,97,281 तथा अब तक कुल 4,76,08,920 डोजें लगायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताहिक संक्रमण दर 3 प्रतिशत से अधिक वाले प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले नागरिकों के लिए विगत 04 दिन की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र जरूरी है। सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण का पालन करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

कोरोना वायरस से संक्रमित 32 नए केस मिले

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 32 नए रोगी मिले और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। संक्रमण अब तेजी से काबू में आ रहा है। 55 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 20 जिलों में इकाई में मरीज मिले। नौ जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसमें अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशांबी, महोबा, मुरादाबाद और श्रावस्ती शामिल हैं। बीते 24 घंटे में 2.51 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई और अब तक कुल 6.55 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है।

सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और नफरत फैला रहे भाजपा के ई–रावण : अखिलेश यादव

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक फायदे के लिए साजिश रचने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को ई–रावण का नाम दिया और कहा कि इनसे निपटने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर 'ई–रावण' की भूमिका में आ गई है और वह रावण की तरह ही भेष बदलकर सोशल

मीडिया पर अफवाह और झूठ फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छद्म रूप में सपा समर्थक बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और सपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करते हैं। मैंने अपनी पार्टी के कैडर से ऐसे छद्म लोगों से सावधान रहने और सोशल प्लेटफार्म पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा है। उन्हें कुछ भी साझा करने, जवाब देने की जरूरत नहीं है बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में पार्टी कार्यालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है। सपा को निशाना बनाकर झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए पार्टी ने पिछले हफ्ते कार्रवाई भी की। सपा प्रमुख के कथित फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर घृणा फैलाने के मामले में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और ट्वीट के स्क्रीन शॉट्स भी दिये जिसमें दावा किया गया था।

हाईस्कूल में 99.53 व इंटर में 97.88 फीसद उत्तीर्ण

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा–12 का परिणाम घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लिखित परीक्षा न होना 55.36 लाख छात्र–छात्राओं के लिए वरदान साबित हुआ। बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाईस्कूल में 99.53 व इंटर में 97.88 फीसद उत्तीर्ण हुए हैं। शनिवार को जारी परिणाम में विशेष फार्मूले के तहत उम्दा अंकों से सफल होने वालों की भरमार है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वर्ष मेरिट जारी नहीं की गई है। दोनों परिणाम अपरान्ह 3:35 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाएं रद कर दी थी। दोनों परीक्षाओं का परिणाम तैयार करने के लिए फार्मूला तय करके उसे जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय ने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा के लिए कुल 29 लाख 96 लाख 31 विद्यार्थी पंजीकृत थे, उनमें से 29 लाख 82 हजार 55 उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 16 लाख 68 लाख 868 छात्र व 13 लाख 13 हजार 187 छात्राएं हैं।

बीएसपी को बड़ा झटका, अखिलेश यादव की शरण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगातार झटका लगता जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरनगर तथा आजमगढ़ को बसपा का गढ़ माना जाता है। इन्हीं दो जगह से बसपा को बड़ा झटका लग रहा है। अम्बेडकरनगर से लालजी वर्मा तथा रामअचल राजभर के पार्टी को छोडने के एलान के बाद अब आजमगढ़ में पार्टी के कद्दावर नेता तथा विधायक सुखदेव राजभर ने सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की काफी प्रशंसा भी की है। आजमगढ़ के दीदारगंज से बहुजन समाज पार्टी के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष

सुखदेव राजभर ने बहुजन समाज पार्टी के खेमे में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। राजभर का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग होने का एलान किया है। बसपा नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखादेव राजभर ने राजनीति से सन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही बसपा को बसपा को मिशन से भटकी हुई पार्टी भी बताया है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने बेटे कमलकांत राजभर के समाजवादी पार्टी में जाने के फैसले को सही बताया है। सुखदेव राजभर के इस कदम से बसपा को आजमगढ़ में झटका लगा है। सुखदेव राजभर ने शनिवार को सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव को भावुक पत्र लिखा है। इसकी कॉपी बसपा अध्यक्ष मायावती को भी है। राजभर ने पत्र में लिखा है कि बीमार हूं। इसी कारण अब सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तीन कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों का किया लोकार्पण

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को राजभवन से चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र लखीमपुर, फिरोजाबाद के प्रशासनिक भवन व दलीप नगर, कानपुर देहात के कृषक प्रशिक्षण सभागार का आनलाइन लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि इससे यहां के वैज्ञानिक प्रशिक्षण व तकनीकी हस्तांतरण संबंधी कार्य सुगमतापूर्वक हो सकेंगे, जिसका लाभ जिले के किसानों को मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर नये स्वरोजगार का सृजन कर गांव स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों में तैनात कृषि विशेषज्ञों को निर्देश दिये कि वे नवीनतम शोधों के आधार पर कृषि प्रदर्शन अपने क्षेत्र में करें। कुलाधिपति ने कृषि विश्वविद्यालयों से कहा कि हर योजना को किसानों तक पहुंचाने में उन्हें मदद करनी होगी।कृषि विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे और स्थानीय रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। उन्हें मंडी में उचित स्थान दिया जाए, किसान अपना उत्पाद अधिक से अधिक ग्राहकों को बेच सकें। आर्गेनिक उत्पाद का कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र सर्टिफिकेशन भी करें।

यूपी में मानव तस्करों का हवाला नेटवर्क भी खंगाल रही एटीएस

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। त्रिपुरा सीमा से बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह के तार हवाला नेटवर्क से भी जुड़े हैं। गिरोह का सरगना मुहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम हवाला के जरिये भी मोटी रकम का लेनदेन करता था। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) अब इस बिंदु पर अपनी जांच को और आगे बढ़ा रहा है। सूबे में पहले फर्जी दस्तावेजों की मदद से पहचान बदलकर रह रहे रोहिंग्या का भी हवाला नेटवर्क सामने आया था। यहां ठेके पर काम करने वाले रोहिंग्या हवाला के जरिये बांग्लादेश व म्यांमार में अपनों को रकम भेज रहे थे। एटीएस दो रोहिंग्या किशोरियों की तस्करी करने के मामले में पकड़े गए बांग्लादेश निवासी मुहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम, म्यांमार के निवासी रहमतउल्ला व शबीउर्रहमान उर्फ शबीउल्लाह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व भी रोहिंग्या को घुसपैठ कराकर उन्हें प्रदेश में ठिकाना दिलाने व फैक्ट्रियों में काम दिलाने वाले कई गिरोह पकड़े जा चुके हैं।

बूम बॉक्स कैफे के बाहर दो युवकों पर जानलेवा हमला

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी की समिट बिल्डिंग में विवाद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिल्डिंग में कैफे खुलने के बाद एक बार फिर वहां विवाद शुरू होने लगे हैं। गुरुवार देर रात में बूम बॉक्स कैफे से पार्टी करके निकल रहे चिनहट निवासी हेमंत सिंह और उनके दोस्त अमन सिंह पर कुछ युवकों ने समिट बिल्डिंग के बाहर हमला बोल दिया। हमले में अमन और हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने हेमंत को अगवा कर लिया और सुलतानपुर रोड पर फेंककर भाग निकले। इंस्पेक्टर विभूतिखंड के मुताबिक हेमंत के पिता शिवनारायण सिंह की तहरीर पर अकबरपुर निवासी हरिओम सिंह उर्फ अंबर और सुलतानपुर निवासी रिषभ सिंह उर्फ रिशू व 10 अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने हेमंत को गुरुवार देर रात में बरामद कर लिया था। आरोपितों की तलाश की जा रही है। शिवशंकर सिंह का आरोप है।

जेपी सेंटर से चोरों ने उड़ाई लाखों की बाथरूम फिटिंग, पार्किंग के बेसमेंट से गायब हुआ सामान

गायत्री विचार ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाया जा रहा जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआइसी) के बनने से पहले ही सामान चोरी होना शुरू हो गया है। निजी कंपनी के कर्मचारी कपिल नायक ने गोमती नगर थाने में 65 पीस बाथरूम शावर व 125 पीस सीपी एंगिल वाल्व गायब होने का मामला दर्ज कराया है। ये सामान मार्क जगुआर कंपनी के हैं, जिनकी बाजार में कीमत लाखों में है। कई वर्षों से चल रहे काम के कारण ये सामान एक स्टोर में रखा था, जिसकी जांच समय–समय पर होती थी। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि सामान चोरी कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विपिन खंड स्थित जेपीएनआइसी के निर्माण का ठेका मेसर्स शालीमार कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2013 में दिया गया था। शालीमार कॉपर्स प्रा. लि. ने वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट का काम मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लंबङ्क्षरग का ठेका मेसर्स गोदरेज एंड बायर्स को दिया था।मंगाया गया सामान निर्माण स्थल के परिसर में रखा गया था। वहीं, कुछ सामान मल्टी स्टोरी पार्किंग के भूमिगत स्थल के परिसर में स्टोर रूम बनाकर रखा गया था।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के लिए जरूरी नही की संपादक की सहमति हो। समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के लिए रिपोर्टर, संवाददाता एवं ब्यूरो स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(हिन्दी दैनिक)
गायत्री विचार

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रांजल मिश्र द्वारा विष्णु ऑफसेट, बायसी की मस्जिद, भानमती चौराहा, हुसैनगंज लखनऊ (उ.प्र.) से मुद्रित एवं 22, रूकमणीपुरम, फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड (226020) लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक – प्रांजल मिश्र, मो0 – 9511422367, **Email - gayatrivichar@gmail.com** (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) **R.N.I. NO - UPHIN/2016/70303**